[श्री प्रमोद महाजन]

कितने भी गठन हम करते रहें उस गठन के बाद भी हनन होता रहेगा। इसलिए इस मानसिकता का सारे राजनीतिक दल अगर निर्माण कर सकें तो मुझे लगता है उसका उपयोग होगा।

मैं गृह मंत्री जी से फिर प्रार्थना तो नहीं करूंगा क्योंकि वह मानने वाले नहीं है क्योंकि एक वर्ष की समय अवधि जो उन्होंने कही है वह मुझे समझ नहीं आती लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण आश्वासन सदन को दिया है कि इस आयोग की जो भी सिफारिशें होंगी वह सामायतः सरकार स्वीकार करेगी, उसको सम्मान देगी। उनके इस आश्वासन को देखते हुए मैंने जो अपना परिनियत संकल्प रखा था सदन से अनुमति चाहूंगा कि वह संकल्प को विद्ड्रा करने की इजाजत दे।

The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now I shall put the motion moved by Shri S.B. Chavan to vote. The question is:

> "That the Bill to provide for the constitution of a National Human Rights Commission, State Human Rights Commissions in States and Human Rights Courts for better protection of human rights and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration." *The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now we will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

SHRI S. MADHAVAN: I am satisfied with the assurance given by the hon. Minister. I do not move any of my amendments.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We now take up clause-by-clause consideration.

Clauses 2 to 43 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S.B. CHAVAN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion w adopted.

THE JUTE MANUFACTURE DEVELOPMENT COUNCI (AMENDMENT) BILL, 1993

THE MINISTER OF STATE IN THi MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLK GRIEVANCES AND PENSIONS ANI THE MINISTER OF STATE IN THI MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sir, I move:

> "That the Bill to amend the Jut Manufactures Development Counci Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken intc consideration."

Sir, the Jute Manufactures Development council set up under the Jute Manufactures Development Council Act, 1983, was following the jute year for its accounting purposes. The jute year is from July to June of the following year. In view of the difficulties that arose out of the differences in the accounting year for the Jute Manufactures Development Council and-the Government of India, it is considered necessary that the Council should also follow the same year for accounting purposes as the Government of India. The proposed Bill seeks to modify the definition of year given in section 2(f) of the Jute Manufactures Development Council Act, 1983 to mean financial year.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I think it is a small amendment and the House can get it passed without any discussion.

SHRIMATI MARGARET ALVA: It was agreed in the Business Advisory Committee also that there will be no discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I think it was

agreed in the Business Advisory Committee that it would be passed without discussion. ..*(Interruptions)*.. I want cooperation of the hon. Members.

SHRIMATI MARGARET ALVA: It was agreed that it would be passed without discussion because it is only an amendment of the definition...

SHRI MOHAMMED AMIN (West Bengal): But if we have to say something, we should get an opportunity. Give me two minutes, at least. ... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay. Shri Mohammed Amin — only two minutes.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): जूट की कृषि की जो हालत है, जूट उद्योग की जो हालत है, उसी पर कुछ कहना चाहेंगे।

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am telling you, it would be wrong because then everybody would like to speak for one or two minutes. ..*(Interruptions)*.. It is only change of the year.

इसके लिए बिजनैस एडवाइजरी कमेटी ने टाइम एलाट नहीं किया है।

श्री मोहम्मद अमीन: जिस सवाल के ऊपर सरकार यह तरमीम लाई है उस एतराज करने को कुछ नहीं है। लेकिन जो असल बात है वह यह है कि सरकार की गलत पालिसी की वजह से जूट की इंडस्ट्री तबाह हो रही है। इसलिए उस सिलसिले में कुछ किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह जो कौंसिल बनाई गई थी, जूट मैनूफेक्चरर्स डेवलपमेंट कौंसिल, इसके काम से जूट का डेवलपमेंट कुछ हो नहीं पाया, खास कर इसलिए कि सिन्थेटिक इसको बर्बाद कर रहा है। हुकूमत की यह पालिसी है कि सिन्थेटिक को ही बढ़ावा मिले। इसकी वजह से जूट के कारखाने बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर हैं, लेकिन ज्यादा कारखाने बंगाल में हैं, ऐसा कोई वक्त नहीं होता है जब 5-7-10 कारखाने बंद न हो। चन्द कारखानों के मालिक मजदूरों को उजरत नहीं देते। प्रोविडेन्ट फण्ड और ई.एस.आई. का पैसा दबा कर मार लेते हैं। बोनस की पैमेन्ट नहीं करते, कारखाने बंद कर देते हैं। बेजा दबाव डालकर मजदूरों के जो हकूक है उनको सलभ कर लेते हैं। इसकी वजह से मजदूरों के अन्दर बहुत ज्यादा बेचैनी है और तमाम ट्रेड युनियनों ने बहुत दिनों से यह मांग की है कि इन सिक मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इसको स्वीकार नहीं करती। हमारी सलाह है कि इसका आखिरी हल यही है। लेकिन जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता तब तक कच्चे पाट की तिजारत के सिलसिले में जे.सी.आई. को मैदान में लाना पड़ेगा। जो सरकारी कारखाने हैं, एन.जे.एम.सी. के, नेशनल जूट मैनूफेक्चरर्स कारपोरेशन के, इन छः कारखानों का प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इसको रोकना चाहिए। अगर ये सारे कदम उठाये गये तो इस उद्योग को बचाया जा सकता है वरना इसको कोई नहीं बचा सकता है।

†[श्री ए.एम. आमीन (पश्चिम बंगाल): जिस सवाल के ऊपर सरकार ये तरमीम लाई है उसमें एतराज करने को कुछ नहीं है। लेकिन जो असल बात है वह यह है कि सरकार की गलत पालिसी की वजह से जूट की इंडस्ट्री तबाह हो रही है। इसलिए उस सिलसिले में कुछ किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह जो कौंसिल बनाई गई थी, जूट मैनूफेक्चरर्स डेवलपमेंट कौंसिल, इसके काम से जूट का डेवलपमेंट कुछ हो नहीं पाया, खास कर इसलिए कि सिन्थेटिक इसको बर्बाद कर रहा है। हुकूमत की यह पालिसी है कि सिन्थेटिक को ही बढ़ावा मिले। इसकी वजह से जूट के कारखाने बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम और उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर हैं, लेकिन ज्यादा कारखाने बंगाल में हैं, ऐसा कोई वक्त नहीं होता है जब 5-7-10 कारखाने बंद न हो। चन्द कारखानों के मालिक मजदूरों को उजरत नहीं देते। प्रोविडेन्ट फण्ड और ई.एस.आई. का पैसा दबा कर मार लेते हैं। बोनस की पैमेन्ट नहीं करते, कारखाने बंद कर देते हैं। बेजा दबाव डालकर मजदूरों के जो हकूक है]†

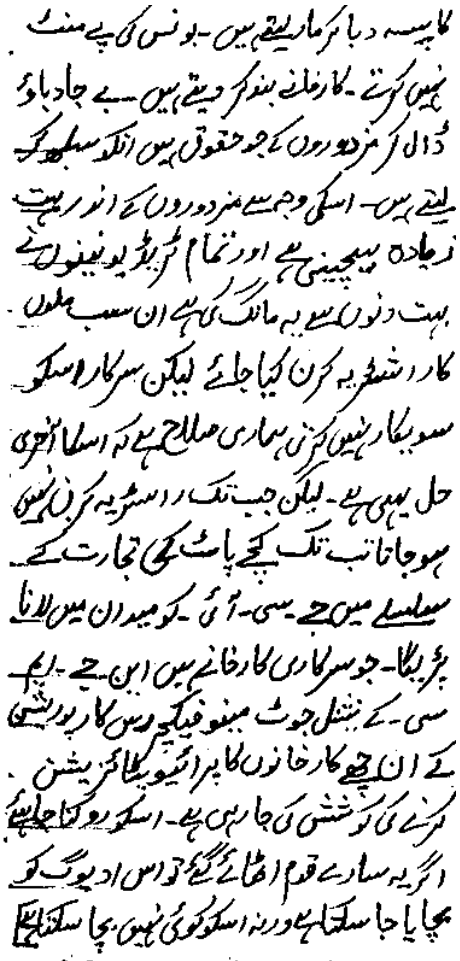

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: श्रीमन्, मैं भी दो मिनट बोलना चाहूंगा। मैं यह मानता हूं कि यह जो संशोधन यहां रखा गया है उसके संबंध में हमारी सहमति है। लेकिन माननीय सदस्य जो बोले हैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। मैं जोड़ना यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को जूट उद्योग की सहायता के लिए जिस तरह से आगे आना चाहिए उस तरह से केन्द्रीय सरकार बिलकुल नहीं आ रही है। 23 जूट मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए बी० आई० एफ० आर० के निकट आवेदन किया गया है। बी० आई० एफ० आर० ने आश्वासन देकर भी कुछ काम नहीं किया। मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में उदार हो कर और सजग होकर काम करना चाहिए। सारे देश में एकमात्र जूट मिल है जो मजदूरों के सहयोग से चलती है। उस सहयोग को हम लोगों ने देखा है। यह मिल पांच करोड़ के करीब प्रति वर्ष लाभ कमा रही है। यह जो न्यू सेन्ट्रल जूट मिल है उसके ब में हम लोगों ने कहा है कि उस पर जो बकाया कर्ज उस कर्ज को मांफ कर दिया जाय, उसका कर्ज कम क दिया जाय। लेकिन भारत सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। मैं भारत सरकार से आवेदन क चाहता हूं कि भारत के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण जूट उद्य की उन्नति के लिए सजगता और सहयोग की भूमि होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे पड़ि बंगाल में अभी ही एक के बाद एक जूट मिलें बंद हो जा रही हैं आगे और हो सकती हैं। जूट उद्योग हम एक प्रमुख शिल्प उद्योग है जिससे हम विदेशी मु कमाते हैं। अगर वह बंद हो गया तो सारा भारतवर्ष क पाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि केन्द्रीय सरकार सी० आई० और बी० आई० एफ० आर० को विशेष रू से निर्देश दे कि जूट के संकट को दूर करने के लिए उदारतापूर्वक कदम उठाये।

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): have to mention one point that t Government of India should direct all t public sector undertakings and, possible, the private sector undertake also to use packaging material made jute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V NARAYANASAMY): Madam, that is a very important point.

श्री रफीक आलम (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, मैं उस इलाके से आता हूं जहां 70 परसेंट जूट का प्रोडक्शन हो रहा है। वहां पर काश्तकारों की हालत रोज-ब-रोज खराब होती जा रही है। उनको मिलने वाला प्राइस बहुत कम है। वह उनकी कैश क्राप है, वहां, किशन गंज गन्ना भी नहीं होता। अब उस जिले में जूट वालों के लिये कोई दूसरा स्कोप नहीं है। उनकी हालत बहुत ही खराब हो रही है। इसीलिये उनको सपोर्ट करने के लिए मैडम इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में किशन गंज जूट मिल सेंक्शन की थी। लेकिन कलकत्ता के जूट मिल-मालिकों और वहां के मौजूदा एम.एल.ए. मिलकर मिल को नहीं बनने दे रहे हैं। मेरी सरकार से, गवर्नमेंट आफ इंडिया से दरख्वास्त है कि किशनगंज जूट मिल को जितनी जल्दी हो सके, उसका फाउन्डेशन स्टोन ले-डाउन हो गया है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है, उस काम को शुरू किया जाय ताकि वहां के काश्तकारों की माली हालत अच्छी हो सके।

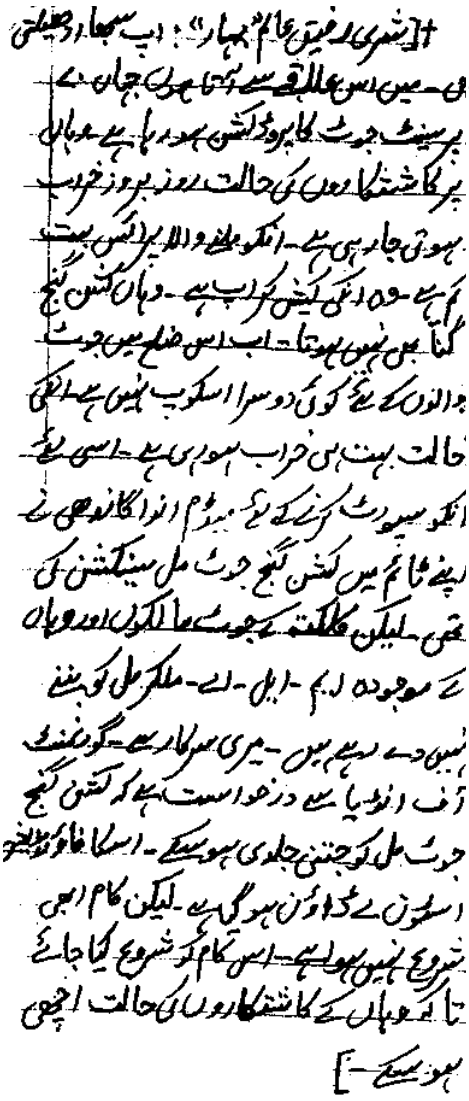

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Only one minute, Sir.

It appears that the jute-grower is getting a raw deal. Even the Minister, Mr. Venkat Swamy, is absent when this Bill is being discussed here. Madam is not a substitute for the Minister of Textiles.

1 would like to add that a lot of concessions have been given to artificial fibre during the recent budget proposals, thereby not only the jute-grower but also the cotton-grower have been attectea tor want of proper policy from the Government. Both the jute and cotton growers are being penalised, giving advantage to artificial-fibre manufacturers and importers, big people like those' of Reliance etc. etc. I would like to advise the Government to set these things right. Unless this is done, no amount of amendments like these will go to solve theproblem.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, the Amendment is actually a simple one. It is just to change the financial

Several points have been made by the Members in the course of the discussion. There are two things to which I would like to respond. One is that there is no proposal to privatise the sick nationalised mills of the National Jute Manufacturing Corporation, I give this assurance. I do know why there is a feeling that this is on the anvil.

I have noted the suggestions made for improving the condition of the jute industry. I realise that the Minister is not here and I cannot be a substitute for him. But, as Minister for Parliamentary Affairs, I suppose we have to step in whenever there is a problem. The Minister of Textiles is at the moment in a tripartite meeting where representatives of all the trade unions and others have come. So, he could not leave the meeting. I offered to pilot this Bill, thinking that there would be no debate and that it was only to be moved and passed.

SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Government ban the use of synthetic packaging material?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I can only say that all the suggestions made will be very carefully studied by the Ministry. I assure you that the Government is concerned about the crisis in tne jute industry, and we will try and Sad out the ways by which these problems can be sorted out. ... *(Interruptions)*

Sir, orders of some sort are being passed to deal with some of these. I am

not going into the details.

But I assure the House that whatever suggestions have been made, will be noted by the Ministry and followed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The question is: "That the Bill to amend the Jute Manufactures Development Council Act, 1983, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration." *The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause *I, the Enacting Formula and the* Title *were added to the Bill.* SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I move:

"That the Bill be passed." *The question was put and the motion ws adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, we take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Need to build a Capital for Haryana

SHRI S.S. SURJEWALA (Haryana): The subject of my Special Mention is Haryana's own capital. Haryana is one of the youngest States. It is also one of the

[Shri S.S. Surje Wala]

smalllest States of the Indian Republic. It was created on 1st November 1966 as a result of the reorganisation of Punjab on linguistic basis. In that way Haryana was created as a byproduct of the State of Punjab.

APthe time of its creation, Haryana was very, backward educationally, culturally, socially and economically. But in the early 70s, Haryana made great strides and achieved the distinction to be the first State in the country where all the villages were linked with metalled roads. It also achieved the distinction of being the first State in the country where all the villages were electrified. There were so many other spheres where it had made great progress. But, alas, by the end of the 70s it had also achieved the dubious distinction to bea State of *Aya Rami and Gaya Rams.*

Twentysix years have already passed and the State of Haryana still remains without a capital of its own. Capital means the identity of the people of the State; capital means a large number of national and international institutions concerning culture, art, science, technology from where the State's entire villages can be enriched by modern education, modern technology, modern culture so that the people of the State can make progress. But, I am very sorry to state that after the lapse of so much time, Haryana, which once was known as a State of action, is now going down. The reason is that without a capital of its own and without a High Court of its own, the people of Haryana are now totally frustrated. Their progress has been retarded. I would like to say that though Haryana had made progress in the field of roads and electricity, yet Haryana's human population still continues to be educationally, socially and culturally very backward. The reason is that Haryana did not have any urban centre or any growth centre where its culture, art and education can flourish. In the absence of that, Haryana did not have its own culture centres, academies, libraries^ museums. The absence of all these things has led to the backwardness of the people. That is why the people of Haryana cannot enjoy the fruits of modern education. They have also been lagging behind in the fields of technology and culture..

Therefore, Haryana people think that they do not want to stay, for a moment, in Chandigarh. Chandigarh may be given to Punjab. But Haryana needs sits own capital. The Government of India is under obligation to provide a State capital for the people of Haryana. Mr. Vice-Chairman, before I conclude, I would like to say that the people of Haryana should not be treated as second class citizens of the country. There is a feeling growing among the people of Haryana that they are being kept deliberately backward. The resources of